आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 25.02.2025
समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से बिना किसी बाधा के साथ पहुंचाने पर जोर दिया।
- उत्तराखंड सरकार, राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों को गोद लेकर उन्हें विकसित करेगी।
- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को यू०सी०सी के तहत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- दून विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

पुस्तक विमोचन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से बिना किसी बाधा के साथ पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिये। राजभवन में ''मेरी योजना केंद्र सरकार'' पुस्तक के विमोचन अवसर पर राज्यपाल ने यह बात कही। इस पुस्तक में उत्तराखण्ड में स्थित केंद्र सरकार के 82 प्रतिष्ठानों की 384 योजनाओं और सेवाओं का संकलन किया गया है। पुस्तक को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.uk.gov.in और संबंधित विभागीय वेबसाइटों पर भी अपलोड किया गया है। यह पुस्तक सिर्फ लाभार्थियों के लिए नहीं, बल्कि शोधार्थियों के लिए भी बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। इससे पहले, वर्ष 2022 में भी यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी, जिसमें राज्य सरकार के 122 विभागों और संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं और सेवाओं का विवरण दिया गया था।

शिक्षण संस्थान विकास

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार, राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों को गोद लेकर उन्हें विकसित करेगी। उन्होंने इस प्रयास में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। राज्य सरकार और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर रावत ने देवभूमि उद्यमिता योजना को छात्र उद्यमिता का एक सफल मॉडल बताया। उन्होंने सीएसआर संगठनों से राज्य के विकास में

सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए, वंचित वर्गों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। कार्यशाला में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने संस्थागत विकास के लिए सीएसआर फंडिंग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकती है। कार्यशाला में, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के प्रतिनिधियों ने उद्यमिता शिक्षा और सीएसआर के योगदान पर विचार–विमर्श किया। उन्होंने विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों में शोध, बुनियादी ढांचे के विकास और स्टूडेंट स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान कई प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और सीएसआर के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग की पहलों में सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उत्तराखंड जजेज एसोसिएशन वार्षिक सम्मेलन

उत्तराखंड जजेज एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन दून विश्वविद्यालय सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया ने सम्मेलन को संबोधित किया।

इस दौरान न्यायमूर्ति धूलिया ने न्यायिक अधिकारियों से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने कहा, कि न्यायपालिका के सामने आने वाले वादकारियों की उम्मीदें होती हैं, और न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे मामलों का शीघ्र निस्तारण करें।

इस दौरान, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेन्दर ने न्यायाधीशों का कर्तव्य त्वरित न्याय प्रदान करना है। उन्होंने लंबित वादों को प्राथमिकता देने पर बल दिया और न्यायिक कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की बात की। सम्मेलन में राज्य के सभी जिला न्यायधीश और न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।

निर्देश

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को राज्य में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए बताया कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी को अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले से इस प्रक्रिया की साप्ताहिक रिपोर्ट गृह सचिव को भेजी जाएगी। मुख्य सचिव ने विभागों में भी नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है, जो अपने विभाग के विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तराखंड के आठ लाख इक्कीस हजार पात्र किसानों के खातों में 181 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। इस योजना की 19वीं किस्त जारी करने के साथ ही सरकार ने अब तक प्रदेश के किसानों को कुल दो हजार नौ सौ छब्बीस करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सरखेत में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न किसान समूहों के पदाधिकारियों को फार्म मशीनरी बैंक के तहत पावर वीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ब्रश कटर, आटा चक्की, चौफ कटर और ट्रैक्टर जैसे उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा, किसानों को सहयोग राशि के चेक भी वितरित किए गए।

समझौता हस्ताक्षर

दून विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत, विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड में स्थित ऑकलैंड विश्वविद्यालय और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, और वैश्विक शिक्षा में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। इन समझौतों के तहत, छात्रों और फैकल्टी के लिए अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दून विश्वविद्यालय और ऑकलैंड विश्वविद्यालय के बीच होने वाली साझेदारी से दोनों संस्थानों के छात्रों को शिक्षा और शोध के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, संयुक्त अकादमिक कार्यक्रमों में क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए छात्र एक हिस्सा दून विश्वविद्यालय में और दूसरा हिस्सा ऑकलैंड विश्वविद्यालय में पूरा कर सकेंगे। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के साथ समझौता बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत, छात्रों को बैंकिंग संचालन, ग्रामीण बैंकिंग, और वित्तीय समावेशन में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिससे वे वास्तविक दुनिया में आवश्यक अनुभव प्राप्त करेंगे।

जादुंग गांव विकास

उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव जादुंग में कायाकल्प की प्रक्रिया तेज हो गई है। पिछले वर्ष से राज्य सरकार ने जादुंग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था, और अब इस परियोजना को गति दी जा रही है। शीतकाल के कारण रुके हुए निर्माण कार्य दो महीने बाद फिर से शुरू किए जाएंगे। गौरतलब है कि जादुंग गांव, जो 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद वीरान हो गया था और अब फिर से अपने पुराने रंग में लौटने की राह पर है। गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है और वहां कई विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। जीएमवीएन ने जादुंग गांव में छह पुराने और जीर्ण–शीर्ण घरों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह कार्य

पिछले साल सितंबर में शुरू किया गया था। इसके अलावा, आठ अन्य घरों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग पांच करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया गया है।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा स्थगित, मार्च में आएंगे पीएम मोदी– अमर उजाला इस शीर्षक के साथ लिखता है– खराब मौसम का कारण टला प्रधानमंत्री का 27 फरवरी को उत्तरकाशी दौरा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी... राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र लिखता है– उत्तराखंड के किसानों के खाते में पहुंचे 181 करोड़। 8 लाख 21 हजार किसानों को मिला लाभ।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण लगातार जारी है... हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण के लिए चलेगा अभियान... मुख्य सचिव ने भेजा सभी जिलाधिकारियों को आदेश पत्र...
उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है... हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– दून समेत चार जिलों में आज बारिश के आसार...28 फरवरी तक बारिश की संभावना।